[2019] 6 एस. सी. आर 577

रूपाली देवी

बनाम्

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(2012 की आपराधिक अपील संख्या 71)

अप्रैल 09,2019

[भारत के मुख्य न्यायाधीश, रंजन गोगोई, एल. नागेश्वर राव और

संजय किशन कौल, न्यायमूर्तिगण]

दंड संहिता, 1860:धारा 498 ए-अधिकारिता-चाहे ऐसे मामले में जहां पति या पत्नि, के रिश्तेदार द्वारा क्रूरता की गई हो और पत्नी वैवाहिक घर छोड़ दें और किसी अन्य स्थान पर स्थित माता-पिता के घर में शरण लें, पत्नी के माता-पिता के घर के स्थान पर स्थित अदालतों को धारा 498 ए के तहत शिकायत पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है।अवधारितः-सामान्य तौर पर, यह वह न्यायालय है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अपराध किया जाता है, जिसके पास प्रश्नगत अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति और अधिकार होगा।दं.प्र.सं. की धारा 179 के तहत यदि किसी आपराधिक कार्य से उत्पन्न होने वाले परिणामों के कारण, किसी अन्य क्षेत्राधिकार में कोई अपराध किया जाता है, तो उस क्षेत्राधिकार में न्यायालय भी संज्ञान लेने के लिए सक्षम होगा-वास्तव में जो निर्धारित किया जाना है वह यह है कि क्या दं.प्र.सं. की धारा 179 के अपवाद का प्रयोग स्थानीय क्षेत्र में स्थित न्यायालयों में अधिकारिता जहां पत्नी का माता-पिता का घर स्थित है-किया जा सकता है धारा-498 में निहित प्रावधाननिस्संदेह पत्नी के मानसिक और शारीरिक कुशलता दोनों को शामिल करता है-यहां तक कि पत्नी की खामोशी में भी एक भावनात्मक संकट और मानसिक पीड़ा हो सकती है। उसके माता-पिता के घर में उसकी पीड़ाएँ हालांकि सीधे उसकेवैवाहिक घर में पति द्वारा क्रूरता के कृत्यों के लिए जिम्मेदार

ठहराया जा सकता है, निस्संदेह, वैवाहिक घर में किए गए कृत्यों के परिणाम होंगे-ऐसे परिणाम, अपने आप में, माता-पिता के घर में किए गए विशिष्ट अपराधों के बराबर होंगे जहां उसने शरण ली है-माता-पिता के घर में मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, हालांकि वैवाहिक घर में किए गए कृत्यों के कारण, धारा 498 ए के अर्थ में माता-पिता के घर में किए गए अपराधों के बराबर होगा। वैवाहिक घर में की गई क्रूरता के परिणामस्वरूप माता-पिता के घर में बार-बार अपराध किए जाते हैं-इस प्रकार के अपराधों पर दं.प्र.सं. की धारा 179 के तहत विचार किया जाता है इसलिए, उस स्थान की अदालतें जहां पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता के कृत्यों के कारण पत्नी घर छोड़ने या वैवाहिक घर से भगा दिए जाने के बाद शरण लेती है, तथ्यात्मक स्थिति पर निर्भर करते हुए, धारा 498 ए-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धाराएँ 177, 178, 179 महिलाओं के खिलाफ अपराध-साक्ष्य अधिनियम, 1972 धारा 113 ए के तहत अपराध करने का आरोप लगाने वाली शिकायत पर विचार करने का अधिकार होगा।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 - इसके अधिनियमन के पीछे का उद्देश्य-पर चर्चा की गई।

शब्द और वाक्यांश -क्रूरता-जिसका अर्थ-चर्चा की गई।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

1.1 अवधारित किया ।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 177 में यह विचार किया गया है कि "प्रत्येक अपराध की जांच और मुकदमा आम तौर पर उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में यह/दायर किया गया था। इसलिए, सामान्य रूप से, यह वह न्यायालय है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अपराध किया जाता है, जिसके पास प्रश्नगत अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति और अधिकार होगा। [पैरा 6] [584-डी]

1.2 धारा 178 किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में अदालतों को अनुमति देकर धारा 177 में उत्कीर्ण "सामान्य नियम" के लिए एक अपवाद पैदा करती है जहां अपराध आंशिक रूप से कारित किया गया है जिसका वह संज्ञान ले सकता है। इसके अलावा यदि एक स्थानीय क्षेत्र में किया गया अपराध दूसरे स्थानीय क्षेत्र में जारी रहता है, तो बाद वाले स्थान की अदालतें मामले का संज्ञान लेने के लिए सक्षम है। धारा 179 के तहत, यदि किसी आपराधिक कार्य से उत्पन्न होने वाले परिणामों के कारण किसी अन्य क्षेत्राधिकार में कोई अपराध किया जाता है, तो उस

क्षेत्राधिकार की अदालत भी संज्ञान लेने में सक्षम होगी।इस प्रकार, यदि कोई अपराध आंशिक रूप से एक स्थान पर और आंशिक रूप से दूसरे स्थान पर किया जाता है या यदि अपराध निरंतर जारी रहता है या जहां किसी आपराधिक कार्य के परिणाम स्वरूप कोई अपराध किसी अन्य स्थान पर किया जाता है, तो 'साधारण नियम' के अपवाद लागू होगा और उन न्यायालयों को, जिनकी अधिकारिता के भीतर आपराधिक कार्य किया जाता है, अपराध का विचारण करने के लिए अनन्य अधिकारिता नहीं होगी। [पैरा 8] [585-ए-डी]

बिहार राज्य बनाम देवकरण नेन्शी (1972) 2 एस. सी. सी. 890:[1973] 3 एससीआर 1004-पर निर्भर था।

2. भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए को आपराधिक कानून (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1983 द्वारा पेश किया गया था।आई. पी. सी. में उक्त संशोधन के अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 174 और 176 के प्रावधानों में भी संशोधन किया गया, जो आत्महत्या से मौत के मामले में पुलिस द्वारा जांच और ऐसी मौतों के कारण के बारे में दंडाधिकारी द्वारा जांच से संबंधित हैं। इसके अलावा पहली अनुसूची में एक संशोधन द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 498ए के तहत अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती बना दिया गया था। आपराधिक कानून (दूसरा संशोधन) 1983 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 113ए की शुरूआत काफी महत्वपूर्ण है कि यह एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के बारे में अनुमान लगाने का प्रावधान करता है यदि ऐसी आत्महत्या विवाहित महिला की शादी की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर की गई थी और वह क्रूरता का शिकार हुई थी। इन संशोधनों के पीछे का उद्देश्य, निस्संदेह, पति और पति के रिश्तेदारों द्वारा पत्नी पर बढ़ती क्रूरता के मामलों का मुकाबला करना था, जिससे पत्नी को आत्महत्या का सहारा लेने या गंभीर चोट की शिकार होना पड़ता है। इसके अलावा पत्नी के उत्पीड़न से निपटने की कोशिश की जाती है ताकि उसे या उसके किसी भी संबंधित व्यक्ति को किसी भी संपत्ति आदि की किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर/नही किया जा सके। [पैरा 12,13] [586-एफ-एच; 587-ए; डी-ई]

3. क्रूरता शारीरिक या मानसिक क्रूरता दोनों हो सकती है। पति या उसके रिश्तेदारों की ओर से खुलेआम किए गए कार्यों से पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव; वैवाहिक घर और उससे दूर जाने का मानसिक तनाव और आघात। आई. पी. सी. की धारा 498ए में दिखाई

देने वाली अभिव्यक्ति "क्रूरता" के अर्थ को समझते हुए दुर्व्यवहार के डर से एक ही घर में वापस जाने की असहायता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पत्नी पर भावनात्मक पीड़ा या मनोवैज्ञानिक प्रभाव, यदि शारीरिक चोट नहीं है, तो वैवाहिक घर छोड़ने और माता-पिता के घर में शरण लेने के बाद भी पत्नी को आघात देना जारी रखना तय है।भले ही वैवाहिक घर में की जाने वाली शारीरिक क्रूरता के कार्य बंद हो गए हों और माता-पिता के घर में इस तरह के कार्य नहीं हुए हों, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि मानसिक आघात और मौखिक आदान-प्रदान सहित पति के कार्यों से होने वाली मनोवैज्ञानिक पीड़ा, यदि कोई हो, जिसने पत्नी को वैवाहिक घर छोड़ने और अपने माता-पिता के साथ शरण लेने के लिए मजबूर किया था, माता-पिता के घर में बनी रहेगी।शारीरिक क्रूरता या अपमानजनक और नीचा दिखाने वाला मौखिक आदान-प्रदान से उत्पन्न मानसिक क्रूरता माता-पिता के घर में जारी रहेगी, भले ही ऐसे स्थान पर शारीरिक क्रूरता का कोई प्रत्यक्ष कार्य न हो। [पैरा 14] [587-जी-एच; 588-ए-सी]

4. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधिनियमन के पीछे का उद्देश्य घरेलू हिंसा की पीड़ितों को आपराधिक कानून में उपचार के खिलाफ एक नागरिक उपचार प्रदान करना है जो आई. पी. सी. की धारा 498ए के तहत प्रदान किया गया है। 2005 के अधिनियम में घरेलू हिंसा की परिभाषा हानि या चोटों पर विचार करता है जो स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, शारीरिक अंग या कल्याण को खतरे में डालते हैं, चाहे मानसिक या शारीरिक, साथ ही भावनात्मक शोषण।उक्त परिभाषा का निश्चित रूप से आई. पी. सी. की धारा 498ए के स्पष्टीकरण ए और बी के साथ घनिष्ठ संबंध होगा जो क्रूरता को परिभाषित करता है। आई. पी. सी. की धारा 498ए में निहित प्रावधान, निस्संदेह, पत्नी के मानसिक और शारीरिक कल्याण दोनों को शामिल करते हैं। हालाँकि माता-पिता के घर में उसकी पीड़ा सीधे तौर पर वैवाहिक घर में पति द्वारा क्रूरता के कृत्यों के कारण हो सकती है, निस्संदेह, वैवाहिक घर में किए गए कृत्यों का परिणाम होगा।इस तरह के परिणाम, अपने आप में, उस माता-पिता के घर में किए गए विशिष्ट अपराधों के बराबर होंगे जहाँ उसने शरण ली है। माता-पिता के घर में मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, हालांकि वैवाहिक घर में किए गए कृत्यों के कारण, माता-पिता के घर में धारा 498ए के अर्थ के भीतर क्रूरता के बराबर होगा। वैवाहिक घर में की गई क्रूरता के परिणामस्वरूप माता-पिता के घर में बार-बार अपराध किए जाते हैं। यह दं.प्र.सं. की धारा 179 के तहत विचार किए गए अपराधों का प्रकार है जो उठाए गए प्रश्न के उत्तर के रूप में वर्तमान मामले पर पूरी तरह से लागू होगा। [पैरा 15] [589-डी-एच; 590-ए]

5. उस स्थान की अदालतों को, जहां पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता के कृत्यों के कारण पत्नी छोड़ने के बाद शरण लेती है या वैवाहिक घर से भगा दी जाती है, तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर, आई. पी. सी. की धारा 498 ए के तहत अपराध करने का आरोप लगाने वाली शिकायत पर विचार करने का भी अधिकार क्षेत्र होगा। [पैरा 16] [589-बी]

वाई. अब्राहम अजीत और अन्य बनाम पुलिस निरीक्षक, चेन्नई और एक अन्य (2004) 8 एससीसी 100:[2004] 3 पूरक।एस. सी. आर. 604; रमेश और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (2005) 3 एस. सी. सी. 507: [2005] 2 एस. सी. आर. 493; मनीष रतन और अन्य बनाम मध्य परेड राज्य और एक (2007) 1 एससीसी 262:[2006] 8 पूरक एससीआर 226; अमरेंदु ज्योति और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य (2014) 12 एससीसी 362; सुजाता मुखर्जी बनाम प्रशांत कुमार मुखर्जी (1997) 5 एससीसी 30:[1997] 3 एससीआर 1127; सुनीता कुमारी कश्यप बनाम बिहार राज्य और एक अन्य (2011) 11 एससीसी 301: [2011] 6 एससीआर 83; एम. पी. बनाम राज्यसुरेश कौशल और एक अन्य (2003) 11 एस. सी. सी. 126-संदर्भित।

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

[2004] 3 पूरक एससीआर 604	संदर्भित किया गया है	कंडिका 3
[2005] 2 एससीआर 493	संदर्भित किया गया है	कंडिका 3
[2006] 8 पूरक एससीआर 226	संदर्भित किया गया है	कंडिका 3
(2014) 12 एससीसी 362	संदर्भित किया गया है	कंडिका 3
[1997] 3 एस. सी. आर. 1127	संदर्भित किया गया है	कंडिका 4
[2011] 6 एससीआर 83	संदर्भित किया गया है	कंडिका 4
(2003) 11 एससीसी 126	संदर्भित किया गया है	कंडिका 4
[1973] 3 एससीआर 1004	पर निर्भर	कंडिका 9

आपराधिक अपील न्याय निर्णयः 2012 की आपराधिक अपील संख्या 71

साथ

2012 की आपराधिक अपील संख्याये- 619,620,621,622 और 623

2007 की आपराधिक विविध रिट याचिका सं. 16456 मामले में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के दिनांकित 03.08.2011 के निर्णय और आदेश से

प्रमोद स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता, अजय कुमार श्रीवास्तव, विक्रांत सिंह बैस, आशुतोष दुबे, संदीप चौधरी, के. उमा शंकर, सुश्री शुभी भारद्वाज, राज किशोर चौधरी, शकील अहमद, अनुपम भाटी, अशोक कुमार श्रीवास्तव, राज शर्मा, सुश्री निधि सिंह दुबे, सुश्री सुंदरी, सुश्री शालू शर्मा, सुभ्रो सान्याल, श्रीमती रेवती राघवन, एस. मुथु कृष्णन, श्रीमती के. शारदा देवी, अमरजीत सिंह धेमान, सुश्री निधि द्विवेदी, सुश्री अलका सिन्हा, सुश्री मालविका त्रिवेदी, अनुव्रत शर्मा, प्रवीण चतुर्वेदी, सुश्री ज्योति चतुर्वेदी, सुश्री अद्यामिश्रा, अभिनव मुखर्जी, सुश्री पूर्णिमा कृष्णा, श्री सुनील कुमार वर्मा, साजू जैकब, सुश्री लिली थॉमस, अभिषेक जायसवाल, गोपाल झा, श्रेयश भारद्वाज, जी. आर. पांडे, श्यामल कुमार, राजेश कुमार चौरसिया, सुनील के. आर., सुश्री आभा आर. शर्मा, डी. एस. परमार, सुश्री सुजीता श्रीवास्तव, महेंद्र सिंह, परमानंद गौर, एकंश बंसल, श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी, बी. एन. दुबे, मुकेश कुमार, जतिंदर कुमार भाटिया, आशुतोष कुमार शर्मा, उग्र शंकर प्रसाद अधिवक्ता।

निर्णय

श्री रंजन गोगोई, भारत के मुख्य न्यायधीश

1. "क्या क्रूरता का गठन करने वाले कृत्यों और आचरण के कारण अपना वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर कोई महिला उन न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के भीतर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकती है और पहुंच सकती है जहां उसे माता-पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शरण लेने के लिए मजबूर किया जाता है।" यह सटीक प्रश्न है जो अपील के इस समूह में अवधारण के लिए उत्पन्न होता है।

2. उपर्युक्त प्रश्न पर इस न्यायालय की राय में तीव्र मतभेद होने के कारण, इसमें ऊपर उपदर्शित प्रश्न पर विचार करने के लिए एक वृहत्तर न्यायपीठ को वर्तमान निर्देश किया गया है।

3. में

(i) अब्राहम अजित और अन्य बनाम पुलिस निरीक्षक, चेन्नई और अन्य (2004) 8 एससीसी 100

(ii) रमेश और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (2005) 3 एससीसी 507

(iii) मनीष रतन और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (2007) 1 एससीसी 262

(iv) अमरेंदु ज्योति और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य (2014) 12 एससीसी 362

यह विचार व्यक्त किया गया है कि यदि किसी वैवाहिक घर में पत्नी के प्रति की गई क्रूरता के कारण वह माता-पिता के घर में शरण लेती है और यदि माता-पिता के घर में क्रूरता का कोई विशिष्ट कार्य पति या उसके नातेदारों द्वारा नहीं किया जा सकता है तो उस क्षेत्र में जहां माता-पिता का घर स्थित है, अधिकारिता रखने वाले न्यायालयों में धारा 498-क के अधीन कार्यवाही आरंभ करना अनुज्ञेय नहीं होगा।उपर्युक्त मामलों में जिस मुख्य तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी वह यह है कि व्यथित पत्नी की ओर से कोई आरोप नहीं लगाया गया था कि वैवाहिक घर छोड़ने के बाद उसके साथ माता-पिता के घर में क्रूरता या उत्पीड़न का कोई प्रत्यक्ष कार्य किया गया था। इन परिस्थितियों में उपरोक्त मामलों में यह विचार व्यक्त किया गया था कि वैवाहिक घर में की गई क्रूरता का अपराध उस माता-पिता के घर में किए गए निरंतर अपराध के बराबर नहीं है जहां व्यथित पत्नी को बाद में स्थानांतरित किया जा सकता है।

4. सुजाता मुखर्जी बनाम प्रशांत कुमार मुखर्जी (1997) 5 एससीसी 30, सुनिता कुमारी कश्यप बनाम बिहार राज्य और अन्य (2011) 11 एससीसी 301 और मध्य प्रदेश राज्य बनामसुरेश कौशल और अन्य (2003) 11 एससीसी 126 में एक अलग दृष्टिकोण अपनाया गया है। तथापि, उक्त मत प्रश्नगत प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों पर आधारित प्रतीत हो सकता है। उदाहरण के लिए, सुजाता मुखर्जी (सुप्रा) में एक विशिष्ट आरोप लगाया गया था

कि पति ने वैवाहिक घर में क्रूरता के कार्य करने के बाद, पत्नी के पैतृक घर में भी चला गया था, जहां उसने शरण ली थी और उस पर हमला किया था। उक्त तथ्यों पर इस न्यायालय ने सुजाता मुखर्जी (पूर्वोक्त) में अभिनिर्धारित किया कि अपराध सुनीता कुमारी कश्यप (पूर्वोक्त) में यह अभिकथन किया गया कि पत्नी के साथ उसके पति द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था जिसने उसे उसके माता-पिता के घर पर छोड़ दिया था और आगे यह कि पति ने उसके बाद उसके बारे में कोई पूछताछ नहीं की थी। यह भी आरोप लगाया गया कि जब पत्नी ने पति से संपर्क करने की कोशिश की, तब भी उसने जवाब नहीं दिया। उक्त तथ्यों में, इस न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि धारा 498-ए के तहत अपराध के परिणाम माता-पिता के घर में हुए हैं और इसलिए, उस स्थान पर अदालत को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 179 के मद्देनजर कथित अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार होगा। सुरेश कौशल (पूर्वोक्त) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि पत्नी के पैतृक घर के स्थान पर न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 179 के अधीन शिकायत पर विचार करने का अधिकार होगा क्योंकि उसके पैतृक घर जबलपुर में उसके साथ क्रूरता की गई थी।

5. उपरोक्त दो विचार, जिन पर विद्वान संदर्भित पीठ ने वर्तमान संदर्भ में कहते समय विचार किया था, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, न्यायालय के समक्ष मामलों के दो समूह विशिष्ट तथ्यों पर आधारित थे। उन मामलों के तथ्यों के आलोक में, जिनमें इस न्यायालय द्वारा ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया था, दोनों विचारों को बनाए रखना संभव हो सकता है। वर्तमान मामले में अदालत को जिस चीज से सामना करना पड़ता है, वह अलग है। क्या ऐसे मामले में जहां पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा वैवाहिक घर में क्रूरता की गई थी और किसी अन्य स्थान पर स्थित पैतृक घर में शरण लेता है, क्या पत्नी के पैतृक घर के स्थान पर स्थित न्यायालयों को धारा 498-क के तहत शिकायत पर विचार करने का अधिकार है?

6. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (दंड प्रक्रिया संहिता) के अध्याय 13 के उपबंधों पर एक नजर डालने की अब आवश्यकता होगी जो जांच और परीक्ष में आपराधिक न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 177 में कहा गया है कि प्रत्येक अपराध की जांच और मुकदमा सामान्यतः उस न्यायालय द्वारा चलाया जाएगा जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में यह किया गया था। अतः यह स्पष्ट है कि सामान्य प्रक्रिया में, यह वह न्यायालय

है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया जाता है, जिसके पास प्रश्नगत अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति और प्राधिकार होगा।

7. धारा 178 और 179 उपर्युक्त नियम के अपवाद हैं और इसे इसके नीचे उपवर्णित किया जा सकता हैः

> "178 जांच या विचारण का स्थान.-
>
> (क) जब यह अनिश्चित हो कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में कोई अपराध किया गया था, या
>
> (ख) जहां अपराध आंशिक रुप में एक स्थानीय क्षेत्र में और आंशिक रुप से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में किया जाता है, या
>
> (ग) जहां कोई अपराध लगातार जारी रहता है और एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में किया जा रहा है, या
>
> (घ) जहां अपराध में विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई आपराधिक कार्य शामिल हैं, वहां ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा इसकी जांच या विचारण किया जा सकता है।"
>
> “179. जहां अपराध किया गया है या अपराध का प्रतिफल हुआ है वहां अपराध विचारणीय है.- जब कोई कार्य किसी ऐसी बात के कारण की गई है जिसके परिणामस्वरूप कोई आपराधिक परिणाम हुआ है, अपराध की जांच या विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसी आपराधिक कार्य की गई है या ऐसा आपराधिक परिणाम हुआ है।"

8. धारा 178 एक अन्य स्थानीय क्षेत्र के न्यायालयों को, जहां अपराध संज्ञान लेने के लिए आंशिक रूप से किया गया है, अनुज्ञात करके धारा 177 में अंतःस्थापित साधारण नियम का अपवाद सृजित करती है।यदि एक स्थानीय क्षेत्र में किया गया अपराध दूसरे स्थानीय क्षेत्र में जारी रहता है तो दूसरे स्थान पर स्थित न्यायालय मामले का संज्ञान लेने के लिए सक्षम होंगे।धारा 179 के तहत, यदि किसी आपराधिक कृत्य से उत्पन्न परिणामों के कारण कोई

अपराध किसी अन्य क्षेत्राधिकार में घटित होता है, तो उस क्षेत्राधिकार में स्थित न्यायालय भी संज्ञान लेने के लिए सक्षम होगा।इस प्रकार, यदि कोई अपराध आंशिक रूप से एक स्थान पर और आंशिक रूप से दूसरे स्थान पर किया जाता है या यदि अपराध निरंतर जारी रहता है या जहां किसी आपराधिक कार्य के परिणाम स्वरूप कोई अपराध किसी अन्य स्थान पर किया जाता है, तो 'साधारण नियम' के अपवाद लागू होगा और उन न्यायालयों को, जिनकी अधिकारिता के भीतर आपराधिक कार्य किया जाता है, अपराध का विचारण करने के लिए अनन्य अधिकारिता नहीं होगी।

9. इस स्तर पर यह ध्यान रखना भी उपयोगी हो सकता है कि निरंतर अपराध समझा जा सकता है। अब यह मुद्दा अनसुलझा नहीं रह गया है और इसका जवाब दे दिया गया है। इस न्यायालय द्वारा बिहार राज्य बनाम देवकरन नेंसी (1972) 2 एससीसी 890 में मामले में। पैरा 5 पर इस बारे में ध्यान दिया जा सकता है।

> "5. एक निरंतर अपराध वह है जो जारी रहने के लिए अतिसंवेदनशील है और जो हमेशा के लिए किया गया है उससे अलग है। यह उन अपराधों में से एक है जो किसी नियम या इसकी आवश्यकता का पालन करने में विफलता से उत्पन्न होता है और जिसमें जुर्माना शामिल होता है, जिसके लिए दायित्व नियम या इसकी आवश्यकता का पालन होने तक जारी रहता है या इसका पालन किया। प्रत्येक अवसर पर जब ऐसी अवज्ञा या गैर-अनुपालन होता है और बार-बार होता है, तो अपराध होता है।दो प्रकार के अपराधों के बीच अंतर किसी ऐसे कार्य या लोप के बीच है जो एक बार और हमेशा के लिए एक अपराध का गठन करता है और एक ऐसा कार्य या लोप जो जारी रहता है और इसलिए हर बार या अवसर पर एक नए अपराध का गठन करता है जब यह जारी रहता है।इस प्रकार निरंतर अपराध के मामले में अपराध को जारी रखने का एक घटक है जो किसी ऐसे अपराध के मामले में अनुपस्थित है जो तब होता है जब कोई कार्य या अपराध एक बार और हमेशा के लिए किया जाता है।"

10. इस प्रश्न का धारा 178 (ख) या (ग) के उपबंधों से कोई संबंध नहीं है।वास्तव में यह अवधारित किया जाना है कि क्या धारा 179 द्वारा बनाए गए अपवाद में स्थानीय क्षेत्र में

स्थित न्यायालयों में अधिकारिता प्रदान करने के लिए कोई आवेदन होगा जहां पत्नी का पैतृक घर स्थित है।

11. उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए व्यक्ति को दंड विधि के उद्देश्यों और कारणों के कथन पर विचार करना होगा [द्वतीय संशोधन अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम 46)] जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता में धारा 498 क अंतःस्थापित की गई थी।इस धारा पर पहली बार ध्यान दिया जा सकता हैः

> "498 क. किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार उस स्त्री के साथ क्रूरता करता है- जो कोई, किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार के रूप में, ऐसी महिला के साथ क्रूरता करता है, उसे तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी भोगी होगा।
>
> व्याख्या - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, '' क्रूरता '' से अभिप्रेत है -
>
> (क) ऐसा कोई जानबूझकर किया गया आचरण जिससे महिला को आत्महत्या करने या गंभीर चोट पहुंचाने या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे वह मानसिक या शारीरिक हो) को खतरा पहुंचाने की संभावना हो. या
>
> (ख) उस महिला को तंग करना जहां ऐसी तंग करने का उद्देश्य उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की किसी विधिविरुद्ध मांग को पूरा करने के लिए विवश करना है या ऐसी मांग को पूरा करने में उसके या उससे संबंधित किसी व्यक्ति के असफल रहने के कारण है।"

12. भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क दंड विधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1983 द्वारा पुरःस्थापित की गई थी। भारतीय दंड संहिता में उपरोक्त संशोधन के अलावा, आत्महत्या के मामले में पुलिस द्वारा जांच और ऐसी मौतों के कारण के बारे में मजिस्ट्रेटों द्वारा जांच से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 174 और 176 के प्रावधानों को भी संशोधित किया गया।धारा 498-क के अधीन अपराधों के अभियोजन के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 198-क भी अंतःस्थापित की गई थी। दंड विधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम,

1983 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 113क का पुरःस्थापन काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें किसी विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के बारे में उपधारणा का उपबंध है, यदि ऐसी आत्महत्या विवाहित महिला के विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर की गई थी और उसके साथ क्रूरता की गई थी। धारा 113ए निम्नलिखित रूप में हैः

> "113-क. किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा - एक विवाहित महिला - जब प्रश्न यह उठता है कि क्या किसी महिला द्वारा आत्महत्या करने के लिए उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार ने उकसाया था और यह दिखाया जाता है कि उसने अपने विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या कर ली थी और उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदार ने उसे क्रूरता से पीड़ित किया था, तो न्यायालय मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगा सकता है कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदार द्वारा की गई थी।
>
> व्याख्या - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, " क्रूरता " का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 498-क में है।"

13. उपरोक्त संशोधन के पीछे का उद्देश्य निःसंदेह, पति और पति के संबंधियों द्वारा पत्नी पर क्रूरता के बढ़ते मामलों का मुकाबला करना था जिससे पत्नी को आत्महत्या या गंभीर चोट पहुंचती है और इसके अलावा पत्नी के उत्पीड़न से निपटने का प्रयास करना था ताकि उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति आदि के लिए किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर किया जा सके। अतः, न्यायिक प्रयास हमेशा आपराधिक विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 द्वारा पुरःस्थापित और अंतःस्थापित विधियों के उपबंधों को, जैसाकि पहले ही देखा जा चुका है, प्रश्नगत उपबंधों को पुरःस्थापित करने के स्पष्ट प्रयोजन प्रश्नगत रखते हुए अधिक प्रभावी और प्रभावी बनाने के लिए होना चाहिए।

14. "क्रूरता" जो भा. दं. सं. की धारा 498क के अधीन अपराध की जड़ है, को ब्लैक लॉ डिक्शनरी में "एक मानव व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार से आक्रोश पैदा होता है (दुर्व्यवहार, अमानवीय व्यवहार, अपमान)। क्रूरता शारीरिक या मानसिक क्रूरता दोनों हो सकती

है। पति या उसके नातेदारों की ओर से प्रत्यक्ष कार्यों द्वारा पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव-वैवाहिक घर से निकाले जाने के मानसिक तनाव और आघात और दुर्व्यवहार किए जाने के भय से उसी घर में वापस जाने की उसकी असहायता-ऐसे पहलू हैं जिन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क में आने वाली 'क्रूरता' अभिव्यक्ति के अर्थ को समझते हुए अनदेखा नहीं किया जा सकता है। पत्नी पर भावनात्मक संकट या मनोवैज्ञानिक प्रभाव, यदि शारीरिक चोट नहीं है, तो वैवाहिक घर छोड़ने और माता-पिता के घर में शरण लेने के बाद भी पत्नी को परेशान करना जारी रहेगा। भले ही वैवाहिक घर में किए गए शारीरिक क्रूरता के कार्य समाप्त हो गए हों और ऐसे कार्य माता-पिता के घर में नहीं होते हों, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि मौखिक आदान-प्रदान सहित पति के कार्यों से उत्पन्न मानसिक आघात और मनोवैज्ञानिक पीड़ा, यदि कोई हो, जिसने पत्नी को वैवाहिक घर छोड़ने और अपने माता-पिता के साथ शरण लेने के लिए मजबूर किया था, माता-पिता के घर में बनी रहेगी। शारीरिक क्रूरता या गाली-गलौज और अपमानजनक मौखिक बहस से पैदा होने वाली मानसिक क्रूरता माता-पिता के घर में जारी रहेगी, भले ही ऐसी जगह पर शारीरिक क्रूरता का कोई प्रत्यक्ष कार्य न हो।

15. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, जैसा कि इसके अधिनियमन के पीछे उद्देश्य इंगित करता है, आपराधिक विधि में उपचार के विपरीत घरेलू हिंसा के पीड़ितों को सिविल उपचार प्रदान करना है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन उपबंधित है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 में घरेलू हिंसा की परिभाषा में ऐसे नुकसान या चोटों की परिकल्पना की गई है जो स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या कल्याण को खतरे में डालते हैं, चाहे वह मानसिक या शारीरिक हो, साथ ही भावनात्मक दुरुपयोग भी हो। उपर्युक्त परिभाषा का भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के स्पष्टीकरण क और ख से निश्चित रूप से संबंध है जो क्रूरता को परिभाषित करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए में निहित प्रावधान निःसंदेह पत्नी के मानसिक और शारीरिक कल्याण दोनों को शामिल करते हैं।यहां तक कि पत्नी की चुप्पी में भी भावनात्मक पीड़ा और मानसिक पीड़ा का अंतर्निहित तत्व हो सकता है। माता-पिता के घर में उसकी पीड़ा, हालांकि वैवाहिक घर में पति द्वारा किए गए क्रूरता के कार्यों के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हो सकती है, निःसंदेह, वैवाहिक घर में किए गए कार्यों के परिणाम होंगे। ऐसे परिणाम, अपने आप में, उस माता-पिता के घर में किए गए विशिष्ट अपराधों के समान होंगे जहां उसने शरण ली है। माता-पिता के घर में मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, हालांकि वैवाहिक घर में किए गए कार्यों के कारण, हमारे

सुविचारित दृष्टिकोण से, माता-पिता के घर में धारा 498-क के अर्थ में क्रूरता करने के बराबर होगा। वैवाहिक घर में की गई क्रूरता के परिणाम स्वरूप पैतृक घर में बार-बार अपराध होते रहते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 179 के तहत इस तरह के अपराधों पर विचार किया गया है, जो उठाए गए सवाल के जवाब के रूप में वर्तमान मामले पर पूरी तरह से लागू होंगे।

16. अतः, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि उस स्थान पर जहां पत्नी पति या उसके नातेदारों द्वारा किए गए क्रूरता के कार्यों के कारण वैवाहिक घर से प्रस्थान करने या दूर भगा देने के पश्चात् आश्रय लेती है, न्यायालयों को भी तथ्यात्मक स्थिति पर निर्भर करते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन अपराधों के किए जाने के अभिकथित परिवाद को ग्रहण करने की अधिकारिता होगी।

17. सभी अपीलों का निपटान उपरोक्त के अनुसार किया जाता है।

[रंजन गोगोई], भारत के मुख्य न्यायाधीश

[एल. नागेश्वर राव], न्यायमूर्ति

[संजय किशन कौल], न्यायमूर्ति

नई दिल्ली

09 अप्रैल, 2019

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।